जिला कलेक्टर और अध्यक्ष विजयनगरम (सामाजिक कल्याण आवासीय विद्यालय सोसायटी) विजयनगरम और अन्य

बनाम

एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी

अप्रैल 20,1990

[कुलदिप सिंह, न्यायाधीश और पी. बी. सावंत, न्यायाधीश]

भारत का संविधान 1950: अनुच्छेद 16-सार्वजनिक सेवाएँ- के लिए भर्ती- विज्ञापन में उल्लिखित योग्यता- जब तक कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो, छूट नहीं।

सिविल सेवाएँः ए.पी. सरकार-ग्रेड 1 और ग्रेड II शिक्षकों की नियुक्ति- विज्ञापन में उल्लिखित योग्यता की उपेक्षा में की गई नियुक्ति-अवैध।

राज्य सरकार द्वारा ग्रेड-I और ग्रेड-II शिक्षक पदों (स्नातकोत्तर शिक्षक और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले एक समाचार पत्र विज्ञापन के अनुसरण में, अपील में प्रतिवादी ने उस पद के लिए आवेदन किया था।

विज्ञापन में निर्धारित योग्यता एम. ए. में द्वितीय श्रेणी की डिग्री थी। हालांकि, एम. ए. में तृतीय श्रेणी की डिग्री रखने वाले प्रतिवादी का चयन किया गया था, और उन्हें हिंदी में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था, जो मूल प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत करने और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन था। जब प्रत्यर्थी ने अपने प्रमाणपत्रों के साथ अधिकारियों से संपर्क किया, तो यह देखा गया कि वह इस पद के लिए योग्य नहीं थी, और इसलिए उसे सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी।

प्रतिवादी ने राहत के लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसने कहा कि यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह योग्य नहीं थी अपीलकर्ताओं ने नियुक्ति का आदेश जारी किया था, और यह कि उसे नियुक्ति के लिए चुना गया था क्योंकि बेहतर अंकों के साथ कोई अन्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, और अपील करने वालों को निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया कि वे प्रतिवादी को ड्यूटी पर आने की अनुमति दें और ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की तारीख से उसके वेतन का भुगतान करें।

अपीलर्थियों ने इस अदालत में अपील की। अपील को अनुमति देते हुए, अभिनिर्धारित किया:

1. जब कोई विज्ञापन किसी विशेष योग्यता का उल्लेख करता है और उस की अवहेलना में नियुक्ति की जाती है, यह केवल नियुक्ति प्राधिकारी और नियुक्त व्यक्ति के बीच का मामला नहीं है। पीड़ित वे सभी लोग हैं जिनके पास नियुक्त व्यक्ति या नियुक्त व्यक्तियों की तुलना में समान या उससे भी बेहतर योग्यता थी, लेकिन जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया था क्योंकि उनके पास विज्ञापन में उल्लिखित योग्यता नहीं थी। [562 एफ]

2. निम्न योग्यताएँ वाले लोगों को नियुक्त करना जनता के साथ धोखाधड़ी के बराबर है जब तक कि विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। [562 जी]

3. धोखाधड़ी वाले व्यवहार को कायम रखने के लिए किसी भी अदालत को पक्षकार नहीं होनी चाहिए। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने वर्तमान मामले में इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया। [562 जी]

4. यह सामान्य जानकारी की बात है कि कभी-कभी या तो गलती से या अन्यथा, चयन समिति के समक्ष रखी गई टिप्पणियों में कार्यालय द्वारा तैयार की गई गलत जानकारी होती है और कभी-कभी चयन समिति इस आधार पर आगे बढ़ती है कि उसके समक्ष उपस्थित होने वाले सभी लोग अन्यथा योग्य हैं। हालांकि, दूसरा चरण जिस पर दस्तावेजों की जांच की जाती है, वह है जब संबंधित उम्मीदवार ड्यूटि को फिर से शुरू करने के लिए मूल प्रमाण पत्रों के साथ उच्च अधिकारियों से संपर्क करता है और वो उनको देखते हैं। यह उस स्तर पर है जब वर्तमान मामले में गलती का पता चला था, और प्रतिवादी को अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी थी। इस तरह की कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं है। [562 बी-सी]

[न्यायालय ने महसूस किया कि प्रतिवादी को इस पड़ाव पर पद से वंचित करना अन्याय होगा, क्योंकि उन्होंने बाद में एम. ए. में एक और डिग्री द्वितीय श्रेणी के साथ प्राप्त की थी और इस तरह खुद को नियुक्त करने के लिए योग्य बनाया, कि वह पद के लिए अधिक उम्र की हो सकती है और कई कम योग्य लोगों को पहले इस पद पर नियुक्त किया गया था, और निर्देश दिया गया था कि उसे शैक्षणिक वर्ष 1990- 1991 की शुरुआत से इस पद पर नियुक्त दी जाये। [563 बी-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2559/1988

(आर. पी. सं 3931/1987 में ए.पी. प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के निर्णय और आदेश दिनांकित 31.8.1987 से।)

अपीलार्थियों की ओर से के. माधव रेड्डी और जी. प्रभाकर।

प्रतिवादी के लिए वाई. पी. राव।

न्यायालय का निर्णय सावंत, न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

1. वर्तमान मामले में स्वीकृत तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी ने सितंबर, 1985 में

ग्रेड-I और ग्रेड-II शिक्षक पदों (क्रमशः स्नातकोत्तर शिक्षक और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पदों) के लिए आवेदन किया, जो उक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले एक समाचार पत्र के विज्ञापन के अनुसरण में था। स्वीकारीय रूप से उक्त पदों के लिए विज्ञापन में लिखी गई योग्यता एम. ए. में द्वितीय श्रेणी की डिग्री थी और प्रतिवादी के पास एम. ए. में तृतीय श्रेणी की डिग्री थी। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि 27 दिसंबर, 1985 को प्रथम अपीलार्थी द्वारा गलत तरीके से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें उसे हिंदी में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन थी। जब आदेश का पालन करते हुए, प्रतिवादी ने प्रमाण पत्र के साथ अधिकारियों से संपर्क किया, तो यह देखा गया कि प्रतिवादी पद के लिए योग्य नहीं था। इसलिए, उन्हें सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें वापस भेज दिया गया।

2. इसके बाद प्रतिवादी ने आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद में संपर्क किया और यह अभ्यावेदित किया कि 27 दिसंबर, 1985 के आदेश के अनुसरण में वह 2 जनवरी, 1986 को वह सेवा में शामिल हो गई थी, और उन्हें उस दिन से ही सभी लाभों के साथ सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायाधिकरण ने 27 दिसंबर, 1985 के आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ताओं को उन्हें सेवा में शामिल होने की अनुमति देने और उनके ड्यूटि पर रिपोर्ट करने की तारीख से उनके वेतन का भुगतान करने का निर्देश देते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया। न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों के खिलाफ हर्जा खर्च भी तय किया ।

3. हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से त्रुटि की है। न्यायाधिकरण द्वारा अपने आदेश के समर्थन में दिए गए कारण हैं, पहला, कि अपीलकर्ताओं ने पूरी तरह से जानते हुए कि वह योग्य नहीं है, नियुक्ति का आदेश

जारी किया था, और दूसरा, कि उसे नियुक्ति के लिए चुना गया था क्योंकि बेहतर अंकों के साथ कोई अन्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था।

4. बहस के दौरान यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि मूल चयन गलती से इस धारणा पर किया गया था कि प्रतिवादी ने विज्ञापन में बताई गई योग्यता-आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था, उन प्रमाणपत्रों की जांच किए बिना जिनकी प्रतियां उसके आवेदन के साथ भेजी गई थीं। चयन समिति ने अनुमान लगाया कि जिन लोगों ने विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया था, उनके पास पदों के लिए आवश्यक योग्यता रही होगी। हालाँकि, प्रतिवादी की नियुक्ति के आदेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रतिवादी को मूल प्रमाण पत्रों के साथ आना चाहिए। जब प्रतिवादी ने उन प्रमाणपत्रों के मूल दस्तावेजों के साथ अपीलकर्ताओं से संपर्क किया, जिनकी जांच की गई थी, तो यह पाया गया कि वास्तव में उसकी योग्यता कम थी। इन परिस्थितियों में उन्हें सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलर्थियों ने प्रतिवादी का चयन इस बोध के साथ किया था कि वह अल्प-योग्य थी। हमारे अनुसार, इस दलील में काफी बल है। यह सामान्य जानकारी में है कि कई बार गलती से या अन्यथा चयन समिति के समक्ष रखी गई टिप्पणियों में कार्यालय द्वारा तैयार गलत डेटा होता है, और कभी-कभी चयन समिति इस आधार पर आगे बढ़ती है कि वे सभी जो उसके समक्ष उपस्थित होते हैं, अन्यथा योग्य हैं। हालांकि, दूसरा चरण जिस पर दस्तावेजों की जांच की जाती है, वह है जब संबंधित उम्मीदवार ड्यूटि को फिर से शुरू करने के लिए मूल प्रमाण पत्रों के साथ उच्च अधिकारियों से संपर्क करता है और वो उनको देखते हैं। यह उस स्तर पर है जब वर्तमान मामले में गलती का पता चला था, और प्रतिवादी को अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी थी। हमें इस तरह की कार्रवाई में कुछ भी गलत नजर नहीं आता है।

5. न्यायाधिकरण का अवलोकन कि बेहतर अंकों के साथ कोई अन्य अभ्यर्थी नहीं था, इन परिस्थितियों में अर्ध सत्य है क्योंकि यह मानते हुए कि उनके पास उन लोगों के बीच बेहतर अंक थे जिन्होंने आवेदन किया था, ऐसा लगता है कि द्वितीय श्रेणी के साथ किसी ने आवेदन नहीं किया था या केवल तृतीय श्रेणी के उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया गया था। यदि ऐसा है तो ये उन तृतीय श्रेणी के उम्मीदवारों के आवेदन पत्र थे जिन्होनें आवेदन किया था और न कि उन सभी के जिन्होंने भी आवेदन किया होता अगर विज्ञापन में यह इंगित होता कि तीसरी श्रेणी की डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं।

6. यह सभी संबंधित लोगों द्वारा आगे महसूस किया जाना चाहिए कि जब विज्ञापन में एक विशेष योग्यता का उल्लेख है और नियुक्ति उसकी अवहेलना में दी जाती है, यह केवल नियुक्ति प्राधिकारी और नियुक्त व्यक्ति के बीच का मामला नहीं है। पीड़ित वे सभी लोग हैं जिनके पास नियुक्त व्यक्ति या नियुक्त व्यक्तियों की तुलना में समान या उससे भी बेहतर योग्यता थी, लेकिन जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया था क्योंकि उनके पास विज्ञापन में उल्लिखित योग्यता नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में निम्न योग्यताएँ वाले लोगों को नियुक्त करना जनता के साथ धोखाधड़ी के बराबर है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। धोखाधड़ी वाले व्यवहार को कायम रखने के लिए किसी भी अदालत को पक्षकार नहीं होनी चाहिए। हमें खेद है कि न्यायाधिकरण इस तथ्य को देख नहीं पाया।

7. हालाँकि, हमें सूचित किया गया है कि प्रतिवादी ने बाद में द्वितीय श्रेणी के साथ एम. ए. में एक और डिग्री प्राप्त की और उक्त पद पर नियुक्त होने के लिए अर्हता प्राप्त की। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के गुण जो भी हों, हम यह नहीं भूल सकते कि वह इस समय तक उस पर भरोसा करने की हकदार थी जहां वह

सफल हुई थी। उन्हें 2 जनवरी, 1986 को सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी और उसके बाद उन्होंने जनवरी 1987 में न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधिकरण का निर्णय 31 अगस्त, 1987 का था और उसके बाद वर्तमान सिविल अपील इस न्यायालय में दिसंबर 1987 से आज तक लंबित थी। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह सेवा करने के लिए मजबूर है, कि उसने आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली है, कि आज वह पद के लिए अधिक उम्र की हो सकती है और आगे तथ्य यह है कि कई अयोग्य लोगों को पहले इस पद पर नियुक्त किया गया था, हम महसूस करते हैं कि इस पड़ाव पर उसे पद से वंचित करना अन्याय होगा। इसलिए, हम न्यायाधिकरण के आक्षेपित आदेश को दरकिनार करते हैं, लेकिन अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी को आगामी शैक्षणिक वर्ष 1990-91 की शुरुआत से ही इस पद पर नियुक्त किया जाये। चूंकि श्री माधव रेड्डी ने तर्क दिया कि वर्तमान में कोई पद खाली नहीं है, इसलिए हम आगे निर्देश देते हैं कि यदि आवश्यक हो, तो उन्हें समायोजित करने के लिए एक पद सृजित किया जाये। हालाँकि, वह अपनी नियुक्ति तक पिछले वेतन सहित किसी भी लाभ की हकदार नहीं होगी।

पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

एन.वी.के.

अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।